Drishti IAS

करेंट अफेयर्स छत्तीसगढ़

(संग्रह)

जून

2023

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

छत्तीसगढ़ **3**

- छत्तीसगढ़ ने पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के मामले में बनाया विश्व रिकार्ड 3
- मुख्यमंत्री ने रीपा उत्पादों की बिक्री के लिये चैट बोट का किया शुभारंभ 4
- छत्तीसगढ़ के संस्कृति विभाग को मिला गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 5
- मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 21.31 करोड़ रुपए की राशि का किया ऑनलाईन अंतरण 7
- पहुँच विहीन ग्रामों के लिये 'डॉक्टर तुमचो दुआर'कार्यक्रम का मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ 8
- राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28 9
- छत्तीसगढ़ में हाथियों के मूवमेंट की हाईटेक मॉनिटरिंग 10
- उद्योग मंत्री ने चेंदरू मंडावी 'द टाइगर बॉय'की प्रतिमा का किया अनावरण 11
- प्रथम खेलो इंडिया जनजाति खेल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ को मिला पदक 12
- मुख्यमंत्री ने 'जल मितान-युवा उद्यमी' उद्यमिता कौशल विकास परियोजना का किया शुभारंभ 12
- प्रथम खेलो इंडिया जनजाति खेल राष्ट्रीय प्रतियोगिता : छत्तीसगढ़ फुटबाल विमेंस टीम ने जीता गोल्ड 14
- गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड कार्यालय का किया शुभारंभ 15
- गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के लिये प्रदेश के आठ अस्पतालों को मिला एनक्यूएएस प्रमाण-पत्र 16
- राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने जीते 15 पदक 17
- 'मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान' का आठवाँ चरण शुरू 17
- राज्य में लघु वनोपज आधारित विकास कार्यों की प्रगति में वृत्त तथा वन मंडलवार जगदलपुर शीर्ष पर 18
- 'मुख्यमंत्री मितान योजना'प्रदेश की सभी 44 नगर पालिकाओं में भी होगी लागू 19
- राज्य शासन ने 15 नवीन शासकीय महाविद्यालय स्थापना को दी स्वीकृति 19
- 'देखो बस्तर सीजन 2-बस्तर ऑन बाइक' 20
- छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग की नवीन पहल : अपीलार्थी सुनवाई के लिये अब मोबाइल से जुड़ सकेंगे 21
- मुख्यमंत्री ने बालवाड़ी योजना के दूसरे चरण में 4318 बालवाड़ियों का शुभारंभ किया 22
- छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने वर्ल्ड बैंक ने मंजूर की 2460 करोड़ रुपए की राशि 23
- देश के आकांक्षी ज़िलों में नारायणपुर को मिला दूसरा स्थान 24
- स्वास्थ्य विभाग और टाटा ट्रस्ट ने मिलकर राज्य के 23 शहरी पीएचसी को बनाया मॉडल हमर अस्पताल 25

नोट :

छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ ने पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के मामले में बनाया विश्व रिकार्ड

चर्चा में क्यों ?

1 जून, 2023 को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा आयोजित मिशन लाईफ कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के 12 लाख 38 हज़ार 116 लोगों ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेकर एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है।

प्रमुख बिंदु

- पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में जनभागीदारी से जागरूकता लाने की छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, ई.आई.ए.सी.पी की यह अभिनव पहल थी, जिसमें एक ही दिन में पर्यावरण संरक्षण के लिये अपने दैनिक जीवन में बदलाव लाने हेतु शपथ का लक्ष्य रखा गया था
- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों से पर्यावरण संरक्षण मंडल के इस अभियान में भागीदारी की अपील करते हुए कहा था कि यह शपथ ही नहीं बल्कि एक जन अभियान है, जो नवा छत्तीसगढ़ में एक कीर्तिमान स्थापित करेगा।
- मुख्यमंत्री की अपील का असर हुआ और राज्य में हर वर्ग के लोगों ने छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की मुहिम में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और एक दिन में 12 लाख 38 हज़ार 116 से अधिक लोगों ने पर्यावरण संरक्षण की शपथ लेकर विश्व रिकार्ड कायम किया।
- रायपुर ज़िले में एक दिन में सबसे अधिक शपथ का विश्व रिकार्ड टूटा और 1 लाख 75 हज़ार 209 शपथ के साथ मंडल ने लिमका बुक ऑफ रिकार्ड में अपना नाम दर्ज कराया।
- साथ ही पूरे राज्य में 12 लाख 38 हज़ार 116 से अधिक लोगों को शपथ दिलाकर इंडिया स्टार बुक ऑफ रिकार्ड एवं वर्ल्ड रिकार्ड बुक में मंडल ने अपना नाम दर्ज कराया।

नोट :

मुख्यमंत्री ने रीपा उत्पादों की बिक्री के लिये चैट बोट का किया शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

1 जून, 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायगढ़ में महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क (रीपा) के तहत विभिन्न प्रकार के उत्पादों के ऑर्डर के लिये चैट बोट का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इस चैट बोट को आत्मिक भारत - vertex suit द्वारा निर्माण एवं फसल बाज़ार के माध्यम और ज़िला प्रशासन रायगढ़ द्वारा एक्टिव किया गया है।
- इस चैट बोट के माध्यम से ग्रामीण औद्योगिक पार्क के उद्यमी अपने उत्पाद को व्हाट्सअप के ज़रिये सीधे ग्राहकों को बेच सकेंगे।
- विदित है कि छत्तीसगढ़ शासन की महत्त्वाकांक्षी योजना 'महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क (रीपा)' के तहत 14 रीपा ग्राम पंचायतों में विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण हो रहा है।
- इनमें जूट के बैग, कोसा के कपड़े, टेराकोटा, जवाफूल चावल, रागी के उत्पाद, बाँस शिल्प, मसाले, रेडी टू ईट, गोबर पेंट, संबलपुरी साड़ी एवं कपड़े, ढोकरा आर्ट, बड़ी पापड़, आर्टिफिशियल ज्वेलरी इत्यादि शामिल हैं।
- चैट बोट उपयोग करने में बहुत आसान है, यह व्हाट्सअप की भाँति ही काम करता है। इस बोट की मदद से ऑर्डर को प्लेस किया जाता है और पेमेंट भी किया जा सकता है।
- यह ग्रामीण उद्यमी के लिये उत्पाद को बेचने में बहुत ही ज्यादा लाभकारी व आसान है। साथ ही रीपा में उत्पादित सामग्रियों को ऑनलाईन बाज़ार जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के माध्यम से ग्राहकों को बेचा जा सकेगा।

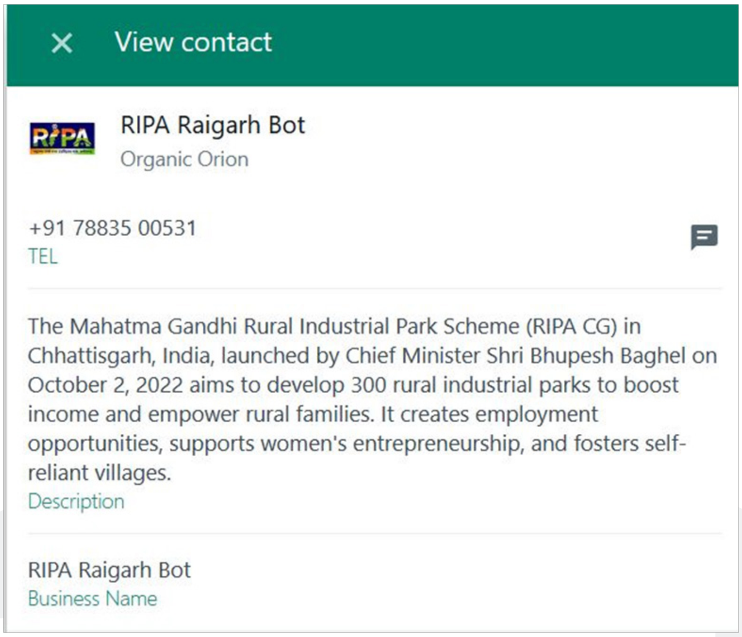

छत्तीसगढ़ के संस्कृति विभाग को मिला गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड

चर्चा में क्यों?

3 जून, 2023 को छत्तीसगढ़ के संस्कृति विभाग को रायगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में लगातार 765 मिनट तक अरण्य कांड पर प्रस्तुति देने के लिये गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में 13 राज्य और 2 अंतर्राष्ट्रीय देशों (कंबोडिया और इंडोनेशिया) के 375 कलाकारों, 17 दलों ने अरण्य कांड पर अलग-अलग भाषा में लगातार 765 मिनट की प्रस्तुति देकर यह विश्व रिकॉर्ड बनाया।
- ज़िला प्रशासन सहित संस्कृति विभाग को मोस्ट स्टेज आर्टिस्ट परफार्मिंग का अवार्ड दिया गया।
- रामायण महोत्सव के सफल आयोजन के लिये रायगढ़ ज़िला प्रशासन को भी अवार्ड दिया गया है, यहाँ 10 हज़ार से अधिक लोगों ने सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया।
- महोत्सव में शामिल कर्नाटक के दल को पहला इनाम 5 लाख रुपए, असम के दल को दूसरा इनाम 3 लाख रुपए और झारखंड के दल को तीसरा इनाम 2 लाख रुपए दिया गया।
- विदित है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की तर्ज पर रायगढ़ में 1 जून से 3 जून तक तीन दिवसीय भव्य राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया गया।

नोट :

मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 21.31 करोड़ रुपए की राशि का किया ऑनलाईन अंतरण

चर्चा में क्यों ?

5 जून, 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को राशि के ऑनलाइन अंतरण के लिये आयोजित कार्यक्रम में हितग्राहियों के खाते में ऑनलाईन 21.31 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की।

प्रमुख बिंदु

- इस राशि में 16 मई से 31 मई तक गौठानों से क्रय किये गए गोबर के एवज में ग्रामीण पशुपालकों के 4.91 करोड़ रुपए तथा गौठान समितियों के 8.98 करोड़ एवं स्व-सहायता समूहों के 6.29 करोड़ रुपए की लाभांश राशि तथा गौठान समितियों के अध्यक्षों और सदस्यों के मानदेय की 1.13 करोड़ रुपए की राशि शामिल है।
- गौरतलब है कि गोबर विक्रेताओं, गौठान समितियों एवं महिला स्व-सहायता समूहों को इस राशि को मिलाकर अब तक 538 करोड़ 89 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इसमें से योजना के प्रारंभ होने के बाद से अब तक गोबर विक्रेताओं को 237.28 करोड़ रुपए तथा स्व- सहायता समूहों एवं गौठान समितियों को 223.60 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है।
- मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में स्वावलंबी गौठान समिति के अध्यक्षों और सदस्यों को मिलाकर समिति के कुल 21 हज़ार 360 सदस्यों की मानदेय की 1.13 करोड़ रुपए की राशि जारी की। स्वावलंबी गौठान समिति के अध्यक्ष को 750 रुपए और अशासकीय सदस्यों को 500 रुपए का मानदेय दिया जा रहा है।

नोट :

- मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कहा कि प्रदेश में 10 हज़ार 409 गौठानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है, इनमें से 98 प्रतिशत, 10 हज़ार 235 गौठानों का निर्माण पूरा हो गया है।
- 4 हज़ार 584 गौठान ऐसे हैं, जिन्होंने पिछले 15 दिनों में 30 क्विंटल या उससे अधिक गोबर की खरीदी की है। इससे पूर्व के पखवाड़े की तुलना में इतनी अधिक मात्रा में गोबर खरीदने वाले गौठानों की संख्या में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार पिछले वर्ष 16 से 31 मई, 2022 की तुलना में इस वर्ष इसी अवधि में गोबर खरीदी में 46 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- प्रदेश के 05 हज़ार 911 गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं। इन गौठानों द्वारा अब तक गोबर खरीदी के एवज में कुल 53 करोड़ 80 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। आज गोबर खरीदी के एवज में जारी की गई 04 करोड़ 91 लाख रुपए की राशि में से 03 करोड़ 05 लाख रुपए का भुगतान स्वावलंबी गौठानों द्वारा तथा विभाग द्वारा 01 करोड़ 86 लाख रुपए का भुगतान किया गया है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि गौठानों में चल रही विभिन्न आजीविका मूलक गतिविधियों से 15 हज़ार 905 स्व सहायता समूहों की 01 लाख 89 हज़ार 614 सदस्यों को अब तक 144 करोड़ 22 लाख रुपए की आय हुई है।
- श्री बघेल ने कहा कि गोधन न्याय योजना का एक उद्देश्य पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करना भी है। राज्य सरकार द्वारा सुराजी गाँव योजना, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, वृक्ष संपदा योजना, कृष्ण कुंज योजना, नदी तट वृक्षारोपण, फलदार पौधा रोपण जैसी योजनाओं के माध्यम से अपने पर्यावरण को लगातार बेहतर बनाने का काम किया जा रहा है।

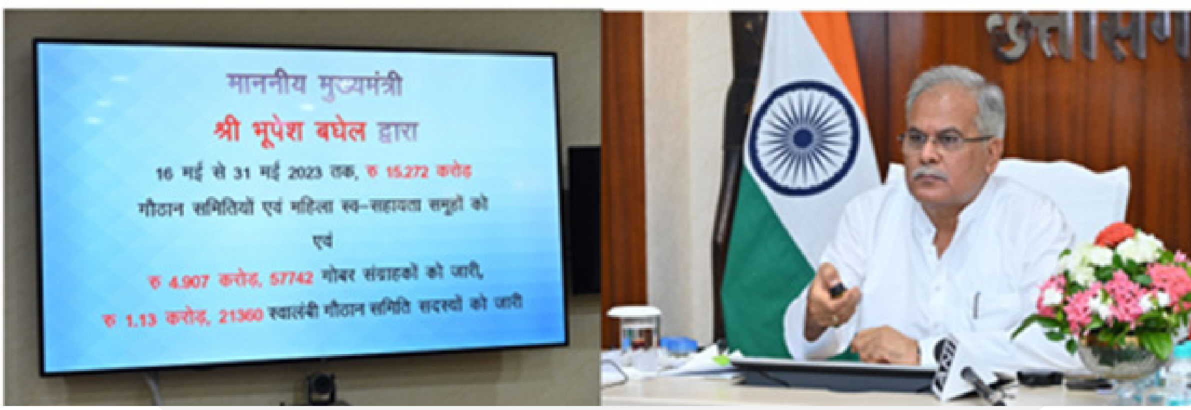

पहुँच विहीन ग्रामों के लिये 'डॉक्टर तुमचो दुआर' कार्यक्रम का मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

6 जून, 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केशकाल विकासखंड के ग्राम बेड़मा में आयोजित कार्यक्रम में ज़िला प्रशासन की नवीन पहल 'डॉक्टर तुमचो दुआर' का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इस पायलेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत ज़िले के बड़ेराजपुर एवं फरसगाँव विकासखंडों के पहुँच विहीन ग्रामों में चिकित्सा सुविधाएँ टेलीमेडिसिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिये एक कॉल सेंटर की स्थापना और कॉल सेंटर में 24 घंटे कर्मचारियों की ड्युटी लगाई जाएगी।
- कॉल सेंटर से कॉल प्राप्त करते ही डॉक्टर, एएनएम एवं अन्य कर्मचारियों से बने दल को सूचित किया जाएगा। डॉक्टर द्वारा बीमार व्यक्ति एवं उनके परिजनों से चर्चा कर टेली कॉन्फ्रेंसिंग से परामर्श दिया जाएगा एवं गंभीर रोगी जिन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता होगी उनके लिये वाहन के साथ डॉक्टर एवं उनका दल घर पहुँचकर रोगी का इलाज करेंगे। आवश्यक होने पर उन्हें अस्पताल लाकर उपचार किया जाएगा।

- विदित है कि ज़िले में दूरस्थ इलाकों में उपचार हेतु हाट बाज़ार क्लिनिक योजना पहले ही सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है। ऐसे में 'डॉक्टर तुमचो दुआर' द्वारा ज़िले के पहुँच विहीन ग्रामों में भी सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने तथा टेलीमेडिसिन के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों तक चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।
- इस योजना के सफल होने पर अन्य विकासखंडों में भी योजना का प्रसार किया जाएगा। यह योजना शासन की सबके लिये समान न्याय, समान सुविधाओं की पहल पर आधारित है।

राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28

चर्चा में क्यों?

6 जून, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने महिलाओं की कार्यकुशलता को एक नई पहचान देने और उन्हें उद्यम से जोड़ने के लिये राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28 लागू की है। इस नीति के तहत महिलाओं को उद्योग स्थापित करने के लिये वित्तीय सहायता (ऋण) देने का प्रावधान किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- इस नीति से महिला कार्यबल में वृद्धि होने के साथ ही उद्योग एवं व्यापार में उनकी सहभागिता बढ़ेगी। तथा महिलाओं के द्वारा शुरू किये गए स्टार्टअप की संख्या में भी तेजी से इजाफा होगा।
- राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28 के तहत महिला उद्यमियों के लिये विनिर्माण उद्यम परियोजनाओं के लिये 50 लाख रुपए तक के ऋण, सेवा उद्यम परियोजनाओं के लिये 25 लाख रुपए तक के ऋण तथा व्यवसाय उद्यम परियोजनाओं के लिये 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिये प्रावधान किया गया है।
- नीति के तहत महिला उद्यमियों द्वारा प्रदेश में स्थापित नवीन, विस्तारीकरण, सूक्ष्म, लघु एवं मध्य विनिर्माण व सेवा उद्यमों को आर्थिक निवेश प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

- उद्यम में किये गए स्थायी पूंजी निवेश का 30-55 प्रतिशत तक स्थायी पूंजी निवेश अनुदान, उद्यमों के लिये प्राप्त किये गए सावधि ऋण तथा परियोजना प्रतिवेदन में प्रावधानित कार्यशील पूंजी (अधिकतम तीन माह की आवश्यकता के बराबर) पर 45 से 70 प्रतिशत और अधिकतम राशि 15 से 60 लाख रुपए तक ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
- नए उद्यमों की स्थापना के लिये 50 प्रतिशत, अधिकतम 75 लाख रुपए तक मार्जिन मनी अनुदान, नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के दिनांक से 6 से 16 वर्षों तक, विद्युत शुल्क, स्टांप शुल्क, परिवहन अनुदान, मंडी शुल्क से छूट दी जाएगी।
- महिला स्व-सहायता समूहों को अतिरिक्त आर्थिक निवेश प्रोत्साहन के रूप में अनुदानों में 5 प्रतिशत का अतिरिक्त अनुदान और छूट के मामलों में 1 वर्ष की अतिरिक्त समयावधि दी जाएगी।
- महिलाओं द्वारा स्थापित स्टार्ट-अप उद्यमों को औद्योगिक नीति 2019-24 के अंर्तगत घोषित स्टार्टअप पैकेज में 5 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान एवं छूट के मामलों में एक वर्ष अतिरिक्त छूट का प्रावधान है।

छत्तीसगढ़ में हाथियों के मूवमेंट की हाईटेक मॉनिटरिंग

चर्चा में क्यों?

7 जून, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ के जंगलों में हाथियों के मूवमेंट की हाईटेक मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। इसके लिये एआई आधारित 'छत्तीसगढ़ एलीफेंट ट्रैकिंग एंड अलर्ट एप' विकसित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- छत्तीसगढ़ के हाथी प्रभावित इलाकों में ग्रामीणों को सतर्क करने के लिये वन प्रबंधन सूचना प्रणाली (एफएमआईएस) और वन्यजीव विंग द्वारा संयुक्त रूप से इस एप को विकसित किया गया है।
- यह एप एलीफेंट ट्रैकर्स (हाथी मित्र दल) से प्राप्त इनपुट के आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पर काम करता है। इस एप का उद्देश्य हाथी ट्रैकर्स द्वारा की जाने वाली 'मुनादी' के अलावा प्रभावित गाँव के प्रत्येक व्यक्ति को मोबाइल पर कॉल, एसएमएस, व्हाट्सएप अलर्ट भेजकर हाथियों की उपस्थिति के बारे में सूचना पहुँचाना है।
- विदित है कि पिछले 3 महीनों से उदंती सीतानदी टाईगर रिजर्व में इस एप का उपयोग किया जा रहा है। 10 किमी. के इलाके में हाथियों के रियल टाईम मूवमेंट का अलर्ट ग्रामीणों के मोबाइल पर सफलतापूर्वक भेजा रहा है।

नोट :

- इस एप में ग्रामीणों के मोबाइल नंबर और जीपीएस लोकेशन का पंजीयन किया जाता है। जब एलीफैंट ट्रैकर्स द्वारा हाथियों के मूवमेंट का इनपुट एप पर दर्ज किया जाता है, तो एप द्वारा स्वचालित रूप से ग्रामीणों के मोबाइल पर अलर्ट पहुँच जाता है।
- हाथी मित्र दल के सदस्य हाथियों के स्थान, झुंड के नाम, व्यवहार और अन्य विशेषताओं को फीड करने के लिये ODK एप (ओपन सोर्स) का उपयोग करते हैं। यह ODK एप ऑनलाइन मोड (रियल टाइम) और ऑफलाइन मोड (करीब-रीयल टाइम जब ट्रैकर मोबाइल नेटवर्क क्षेत्र से बाहर होते हैं) दोनों में काम करता है।
- अलर्ट एवं ट्रैकिंग एप द्वारा समय अवधि फिल्टर का उपयोग करके हाथियों की उपस्थिति वाले मार्ग को ट्रैक कर, हाथियों के झुंड को फिल्टर किया जा सकता है और अलग-अलग मार्गों को ट्रैक किया जा सकता है (जैसे-सिकासार दल, चंदा दल आदि)।
- इस एप का उपयोग केवल हाथी ही नहीं, अन्य माँसाहारी, सर्वाहारी जानवर (तेंदुआ, सुस्त भालू), मैना, जंगली भैंसों की उपस्थिति का भी अलर्ट भेजने, अनुसंधान हेतु, आवास विकास, आवश्यकता के अनुसार योजना बनाने, ट्रैक करने में किया जा सकता है।

उद्योग मंत्री ने चेंदरू मंडावी 'द टाइगर बॉय' की प्रतिमा का किया अनावरण

चर्चा में क्यों?

8 जून, 2023 को छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने राज्य के नारायणपुर ज़िले के 'टाइगर बॉय' के नाम से प्रसिद्ध चेंदरू मंडावी की प्रतिमा का अनावरण ज़िला मुख्यालय नारायणपुर के नया बस स्टैंड चौक एवं ग्राम पंचायत गढ़बेंगाल में किया।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि 'टाइगर बॉय' के नाम से प्रसिद्ध चेंदरू मंडावी का जन्म नारायणपुर ज़िले के ग्राम गढ़बेंगाल में हुआ था। उनकी दोस्ती बाघ (टेंबु) से होने के कारण वह 'टाइगर बॉय' के नाम से प्रसिद्ध था।
- स्वीडन के फिल्म निर्देशक अरने सक्सहार्फ द्वारा चेंदरू और बाघ की दोस्ती पर बनाई गई फिल्म 'द जंगल सागा' को 1997 में ऑस्कर अवार्ड प्राप्त हुआ। इस फिल्म से चेंदरू मंडावी की ख्याति पूरे विश्व में फैल गई।

- विदित है कि चेंदरू स्वीडन में भी एक वर्ष रहे। अपने जीवन के अंतिम समय में वे अपने गाँव में ही रहे, जहाँ 78 वर्ष की आयु में 18 सितंबर 2013 को उनका निधन हुआ।
- उद्योग मंत्री ने इस अवसर पर गढ़बेंगाल स्थित पार्क का निरीक्षण भी किया, जहाँ बच्चों के खेलने के लिये सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं।

प्रथम खेलो इंडिया जनजाति खेल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ को मिला पदक

चर्चा में क्यों?

11 जून, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ओडिशा के भुवनेश्वर में प्रथम खेलो इंडिया जनजाति खेल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को विभिन्न स्पर्धाओं में पदक मिले हैं।

प्रमुख बिंदु

- प्रतियोगिता में आवासीय तीरंदाजी अकादमी बिलासपुर तथा एथलेटिक अकादमी के खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं।
- आवासीय तीरंदाजी अकादमी बिलासपुर के कुबेर सिंह को 30 मीटर में सिल्वर मेडल मिला है और ओवर ऑल चैंपियनशिप में वे दूसरे पोजीशन में रहे हैं। इसी तरह से आवासीय एथलेटिक अकादमी बिलासपुर की खिलाड़ी कुमारी तर्निका टेटा ने 100 मीटर वीमेंस स्पर्धा में रजत पदक जीता है।
- प्रतियोगिता में आयोजित हुए विमेन फुटबॉल सेमीफाइनल में छत्तीसगढ़ की टीम ने त्रिपुरा को 4-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल मैच छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच खेला जाएगा।
- इस प्रतियोगिता में बालिका फुटबॉल एकेडमी रायपुर की खिलाड़ी किरण पिस्दा ने तीन गोल किये जबकि बस्तर की पिंकी कश्यप ने एक गोल किया।
- उल्लेखनीय है कि भुवनेश्वर में आयोजित हो रही इस प्रतियोगिता में 18 राज्यों के 5000 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने 'जल मितान-युवा उद्यमी' उद्यमिता कौशल विकास परियोजना का किया शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

12 जून, 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री निवास में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में पेयजल योजनाओं के संचालन और स्थायी रख-रखाव के लिये अपने तरह के पहले और अनूठे कार्यक्रम 'जल मितान-युवा उद्यमी' उद्यमिता कौशल विकास परियोजना का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इसके तहत ग्रामीण अंचलों में कुशल जल मितानों की उपलब्धता हेतु जल जीवन मिशन और यूनिसेफ की सहभागिता से प्रारंभ किये गए। इस कार्यक्रम के तहत प्रदेश में 58 हज़ार ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है।
- इस कार्यक्रम के ग्रामीण युवाओं को जल गुणवत्ता परीक्षण सर्विसेज, नल-पाइप फिटिंग रिपेयरिंग, आरो फिटिंग-रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिकल फिटिंग-रिपेयरिंग, सोलर पैनल फिटिंग-रिपेयरिंग, पंप आपरेटर सर्विस आदि ट्रेडों में 21 दिन का आवासीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्र कुमार ने कार्यक्रम में प्रतीक स्वरूप प्रशिक्षण प्राप्त 90 जल मितान एवं युवा उद्यमियों को नि:शुल्क टूल किट प्रदान किये।
- 15 हज़ार रुपए की कीमत के टूल किट में युवाओं को सुरक्षा जूता, हेलमेट तथा उपकरण आदि दिये गए हैं। राज्य के 540 युवाओं तथा 90 युवा उद्यमियों को 21 दिनों की उच्च स्तरीय आवासीय ट्रेनिंग दी गई है।
- मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जहाँ जल जीवन मिशन के तहत पेयजल योजनाओं के संचालन और संधारण के लिये बड़ी संख्या में ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उन्हें जल मितान, युवा उद्यमी तथा जल दीदी के रूप में योजनाओं के संधारण और संचालन के लिए तैयार किया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि 'जल जीवन मिशन' के तहत छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र के 50 लाख घरों में नल जल कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके तहत अब तक 24 लाख घरों में नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं।
- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन ने कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में संचालित नल-जल योजनाओं के संधारण और संचालन के लिये 'जल जीवन मिशन' के अंतर्गत यूनिसेफ के सहयोग से पूरे प्रदेश में 58 हज़ार युवाओं को जल मितान के रूप में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसमें से ग्राम पंचायतों की अनुशंसा पर 11 हज़ार युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
- यूनिसेफ की वाटर एंड सेनिटेशन, हाईजिन विशेषज्ञ सुश्री श्वेता पटनायक ने कहा कि छत्तीसगढ़ 'जल मितान' कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है। छत्तीसगढ़ में पंचायत स्तर पर जल आपूर्ति योजनाओं के स्थायी रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिये इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम बहुकुशल और उद्यमिता मॉडल के माध्यम से पेयजल संरचनाओं के रखरखाव के लिये 'वन स्टॉप सॉल्यूशन' की अवधारणा पर आधारित है।

नोट :

प्रथम खेलो इंडिया जनजाति खेल राष्ट्रीय प्रतियोगिता : छत्तीसगढ़ फुटबाल विमेंस टीम ने जीता गोल्ड

चर्चा में क्यों ?

12 जून, 2023 को ओडिशा के भुवनेश्वर में प्रथम खेलो इंडिया जनजाति खेल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ और झारखंड के विमेंस फुटबाल टीम के बीच खेले गए फाइनल मैच में छत्तीसगढ़ की टीम ने झारखंड को टायब्रेकर में 2-0 से हराकर गोल्ड मैडल अपने नाम कर लिया।

प्रमुख बिंदु

- फाइनल मुकाबले में दोनों टीमें ने मैदान में अपना पूरा दमखम दिखाया, लेकिन निर्धारित समय में दोनों ही टीमें कोई गोल नहीं कर सकीं और मैच का परिणाम टायब्रेकर से निकला। टायब्रेकर में दोनों टीमों को पाँच-पाँच स्ट्रोक लगाने का मौका दिया गया।

- मैच में बालिका फुटबॉल अकादमी रायपुर में अभ्यासरत खिलाड़ी किरण पिस्दा ने टायब्रेकर में गोलकीपर की जिम्मेदारी निभाते हुए विरोधी टीम को गोल करने का एक भी मौका नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ टीम से टायब्रेकर में स्वयं किरण पिस्दा और बस्तर की मुस्कान ने 1-1 गोल कर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया।
- इसके पहले 11 जून को छत्तीसगढ़ की विमेंस फुटबाल टीम ने दमदार प्रदर्शन करते हुए विमेन फुटबॉल सेमीफाइनल में त्रिपुरा को 4-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। सेमीफाइनल में बालिका फुटबॉल एकेडमी रायपुर की खिलाड़ी किरण पिस्दा ने तीन गोल, जबकि बस्तर की पिंकी कश्यप ने एक गोल किया था।
- गौरतलब है कि खेलो इंडिया जनजाति खेल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है। प्रतियोगिता में आवासीय तीरंदाजी अकादमी बिलासपुर के कुबेर सिंह को 30 मीटर में सिल्वर मेडल मिला और वे ओवरऑल चैंपियनशिप में दूसरे पोजीशन में रहे। इसी तरह आवासीय एथलेटिक अकादमी बिलासपुर की खिलाड़ी कुमारी तर्निका टेटा ने 100 मीटर वीमेंस स्पर्धा में रजत पदक प्राप्त किया।
- उल्लेखनीय है कि भुवनेश्वर में आयोजित इस प्रतियोगिता में 18 राज्यों के 5000 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं।

गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड कार्यालय का किया शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

12 जून, 2023 को छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने राजधानी रायपुर के गौतम नगर में 'छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड' कार्यालय का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि केश शिल्प एक परांपरागत व्यवसाय के रूप में प्रचलित है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस व्यवसाय में संलग्न संवर्ग के समग्र विकास को सुनिश्चित करने, कल्याणकारी योजना बनाए जाने, केश शिल्प में नवीन तकनीक विकसित करने और शासन एवं संवर्ग के बीच समन्वय स्थापित किये जाने का निर्णय लिया है।
- केश शिल्प से जुड़े संवर्ग के हित के लिये सामाजिक-आर्थिक नीति तैयार किये जाने हेतु समाज कल्याण विभाग अंतर्गत 'छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड' का गठन किया गया है।
- 'छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड' कार्यालय गुलाब नगर तीसरी गली, गौतम विहार, अमलीडीह रोड देवपुरी में स्थित है।

नोट :

गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के लिये प्रदेश के आठ अस्पतालों को मिला एनक्यूएएस प्रमाण-पत्र

चर्चा में क्यों?

13 जून, 2023 को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने वाले राज्य के आठ स्वास्थ्य केंद्रों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (NQAS–National Quality Assurance Standard) प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने विगत अप्रैल से मई माह के बीच इन आठ अस्पतालों का निरीक्षण कर मरीजों के लिये उपलब्ध सेवाओं की गुणवत्ता का परीक्षण किया था। टीम ने इस संबंध में मरीजों से भी फीडबैक लिया था।
- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मझगाँव उप स्वास्थ्य केंद्र (बिलासपुर), दुल्ला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (गरियाबंद), कलचा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (बस्तर), पीपरोल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (बलरामपुर), पीथमपुर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (गौरेला-पेंड्रा-मरवाही), ससहा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (बलौदा बाज़ार) तथा शिवप्रसाद नगर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर व दकई हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (सरगुजा) को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण-पत्र से नवाज़ा है।
- स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम के मूल्यांकन में मझगाँव उप स्वास्थ्य केंद्र को 81 प्रतिशत, दुल्ला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को 82 प्रतिशत, कलचा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को 89 प्रतिशत, पीपरोल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को 73 प्रतिशत, पीथमपुर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को 89 प्रतिशत, शिवप्रसाद नगर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को 93 प्रतिशत, ससहा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को 96 प्रतिशत एवं दकई हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को 88 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं।
- उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण-पत्र प्रदान करने के पूर्व विशेषज्ञों की टीम द्वारा अस्पताल की सेवाओं और संतुष्टि स्तर का विभिन्न मानकों पर परीक्षण किया जाता है। इनमें उपलब्ध सेवाएँ, मरीजों के अधिकार, इनपुट, सपोर्ट सर्विसेस, क्लिनिकल सर्विसेस, इन्फेक्शन कंट्रोल, गुणवत्ता प्रबंधन और आउटकम जैसे पैरामीटर शामिल हैं। इन कड़े मानकों पर खरा उतरने वाले अस्पतालों को ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता प्रमाण-पत्र जारी किये जाते हैं।

नोट :

राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने जीते 15 पदक

चर्चा में क्यों?

9 से 12 जून, 2023 तक ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित प्रथम जनजातीय राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने 1 स्वर्ण, 6 रजत, 8 काँस्य मिलाकर कुल 15 पदक अपने नाम किया।

प्रमुख बिंदु

- ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित प्रथम जनजातीय राष्ट्रीय खेल स्पर्धा में 18 राज्यों के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा और खेल कौशल का प्रदर्शन किया।
- छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 50 मीटर तैराकी में रजत और 100 मीटर में काँस्य पदक जीता।
- छत्तीसगढ़ की फुटबॉल बालिका टीम ने गोल्ड मैडल जीतकर अपना लोहा मनवाया।
- खो-खो बालिका टीम और कबड्डी बालिका टीम को काँस्य पदक मिला।
- एथलेटिक्स के ऊँची कूद इवेंट में तानिया ने काँस्य पदक, 100 मीटर दौड़ में बिलासपुर के बहतराई आवासीय खेल अकादमी की तर्नीका टेटा ने रजत पदक और लंबी कूद में काँस्य पदक प्राप्त किया। 5000 मीटर दौड़ में पुरुष वर्ग में मनीष मांडवी ने रजत पदक तथा बालिका वर्ग में प्रमिला मांडवी ने रजत पदक हासिल किया।
- तीरंदाजी में बिलासपुर के बहतराई आवासीय खेल अकादमी के कुबेर सिंह जगत ने व्यक्तिगत 30 मीटर में रजत पदक तथा व्यक्तिगत ओवर ऑल में रजत पदक अपने नाम किया।
- मिक्स इवेंट में कुबेर सिंह और बुंदेश्वरी मरावी ने काँस्य पदक जीता। वहीं, तीरंदाजी के टीम चैंपियनशिप में बालिकाओं ने काँस्य पदक और बालक तीरंदाजी टीम ने रजत पदक हासिल किया।

'मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान' का आठवाँ चरण शुरू

चर्चा में क्यों?

15 जून, 2023 को प्रदेश में 'मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान' का आठवाँ चरण शुरू हुआ। इसके साथ ही राज्य में 'सघन कुष्ठ रोग अभियान' और 'राष्ट्रीय नेत्र ज्योति अभियान' भी शुरू हुआ।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि मलेरिया के मामलों को निम्नतम स्तर तक ले जाकर पूर्ण मलेरिया मुक्त राज्य के लक्ष्य को हासिल करने के लिये प्रदेश में लगातार इस अभियान को चलाया जा रहा है।
- बस्तर संभाग के सभी सातों ज़िलों सहित प्रदेश के कुल 23 ज़िलों में 15 जून से 10 जुलाई (25 दिनों) तक यह अभियान संचालित किया जाएगा। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा करीब 22 लाख लोगों की मलेरिया जाँच की जाएगी।
- प्रदेश के सभी 33 ज़िलों के 146 विकासखंडों में 'राष्ट्रीय नेत्र ज्योति अभियान' व 'सघन कुष्ठ खोज अभियान' भी संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। इस दौरान कुष्ठ के संदेहास्पद रोगियों की पहचान कर जाँच व उपचार किया जाएगा। अभियान के दौरान नेत्र रोगियों की पहचान कर समुचित इलाज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
- मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के आठवें चरण में प्रदेश के लगभग 22 लाख लोगों की मलेरिया जाँच का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिये प्रदेश भर में 2854 टीमों का गठन किया गया है। मलेरिया से ज्यादा प्रभावित बस्तर संभाग में 1539 और अन्य 16 ज़िलों में 1315 टीमें बनाई गई हैं।
- अभियान के दौरान 274 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और 904 उप स्वास्थ्य केंद्रों के अंतर्गत मलेरिया की जाँच व उपचार के लिये दल सक्रिय रहेंगे। अभियान के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम और मितानिनें घर-घर जाकर मलेरिया की जाँच करेंगी।
- सर्वे दलों द्वारा मलेरिया से बचाव के लिये लोगों को जागरूक कर उन्हें मच्छरदानी के नियमित उपयोग के लिये प्रेरित किया जाएगा। इस दौरान गाँवों में घरों के आसपास जमा पानी और नालियों में बीटीआई व जले हुए तेल का छिड़काव भी किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की टीम सभी घरों में कुष्ठ और नेत्र रोगों के संभावित मरीजों की भी जानकारी लेंगी।
- उल्लेखनीय है कि मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के पहले सात चरणों में कुल एक करोड़ 41 लाख मलेरिया जाँच की गई हैं। इस दौरान पॉजिटिव पाए गए एक लाख 49 हज़ार मरीजों को तत्काल इलाज उपलब्ध कराया गया।
- स्वास्थ्य विभाग की टीम ने घर-घर जाकर पहले चरण में 14 लाख छह हज़ार, दूसरे चरण में 23 लाख 75 हज़ार, तीसरे चरण में 15 लाख 70 हज़ार, चौथे चरण में 19 लाख 98 हज़ार, पाँचवें चरण में 14 लाख 36 हज़ार, छठवें चरण में 43 लाख 61 हज़ार और सातवें चरण में नौ लाख 34 हज़ार लोगों की मलेरिया जाँच की है।
- इस दौरान पहले चरण में पॉजिटिव पाए गए 64 हज़ार 646, दूसरे चरण में 30 हज़ार 076, तीसरे चरण में 16 हज़ार 148, चौथे चरण में 11 हज़ार 363, पाँचवे चरण में 11 हज़ार 321, छठवें चरण में 7479 एवं सातवें चरण में 7974 मलेरिया पीड़ितों का तत्काल उपचार किया गया।

राज्य में लघु वनोपज आधारित विकास कार्यों की प्रगति में वृत्त तथा वन मंडलवार जगदलपुर शीर्ष पर

चर्चा में क्यों?

17 जून, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज आधारित विकास कार्यों की प्रगति में वित्तीय वर्ष 2022-23 अंतर्गत वृत्त तथा वन मंडलवार जगदलपुर शीर्ष पर है।

प्रमुख बिंदु

- जानकारी के अनुसार राज्य के सभी 6 वनवृत्तों और वन मंडलों में लघु वनोपज आधारित विकास कार्यों की रैंकिंग में जगदलपुर को प्रथम स्थान हासिल हुआ है।
- प्रबंध संचालक राज्य लघु वनोपज संघ अनिल राय से प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें वृत्तवार प्रथम जगदलपुर के पश्चात् रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कांकेर तथा सरगुजा का स्थान है।
- इसी तरह ज़िला यूनियनवार रैंकिंग में प्रथम जगदलपुर के पश्चात् कटघोरा तथा बालोद का स्थान है। इसके पश्चात् क्रमश: बलौदाबाज़ार, धमतरी, गरियाबंद, कवर्धा, दंतेवाड़ा पूर्व भानुप्रतापपुर, राजनांदगाँव, कांकेर, बिलासपुर, महासमुंद, बलरामपुर, सुकमा, धरमजयगढ़, खैरागढ़, बीजापुर, कोरबा, नारायणपुर, सूरजपुर, रायगढ़, दक्षिण कोंडागाँव, सरगुजा, जशपुर, मनेंद्रगढ़, पश्चिम भानुप्रतापपुर, केशकाल, कोरिया तथा मरवाही का स्थान है।

नोट :

- प्रबंध संचालक अनिल राय के अनुसार लघु वनोपज आधारित विकास कार्यों के अंतर्गत संग्रहण, प्रसंस्करण, विपणन, लाख पालन, औषधि परियोजना तथा वित्तीय प्रगति के आधार पर प्रत्येक वृत्त और ज़िला यूनियन द्वारा किये गए कार्यों की समीक्षा कर उक्त रैंक निर्धारित की गई है।

'मुख्यमंत्री मितान योजना' प्रदेश की सभी 44 नगर पालिकाओं में भी होगी लागू

चर्चा में क्यों ?

19 जून, 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आम नागरिकों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए घर-बैठे प्रमाण-पत्र तथा आवश्यक शासकीय दस्तावेज़ बनवाने के लिये संचालित लोकप्रिय 'मुख्यमंत्री मितान योजना' को प्रदेश की सभी 44 नगर पालिकाओं में लागू करने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु

- 'मुख्यमंत्री मितान योजना' वर्तमान में प्रदेश के 14 नगर निगमों में संचालित है। इस योजना की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 01 मई, 2022 से लागू इस योजना का लाभ अब तक 96,258 नागरिक उठा चुके हैं।
- मुख्यमंत्री की पहल पर इस योजना के लागू होने के बाद से नागरिकों को ज़रूरी प्रमाण-पत्र और शासकीय दस्तावेज़ बनवाने के लिये नगर निगम, तहसील तथा अन्य सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने के आवश्यकता नहीं रह गई है।
- इस योजना के तहत अब तक 96 हज़ार 258 नागरिकों को उनकी आवश्यकता के शासकीय दस्तावेज़ घर-बैठे प्रदान किये जा चुके हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिये अब तक 01 लाख 13 हज़ार 234 नागरिकों द्वारा टोल फ्री 14545 नंबर पर सरकारी दस्तावेज़ बनवाने के लिये कॉल किये गए हैं।
- योजना के लागू होने से वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, मज़दूरों, किसानों, महिलाओं और आम नागरिकों को काफी सहूलियत हो गई है।
- मितान योजना के अंतर्गत घर-बैठे मूल निवासी प्रमाण-पत्र, अनुसूचित जाति जनजाति प्रमाण-पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, भूमि रिकॉर्ड की नकल, मृत्यु प्रमाण-पत्र, विवाह पंजीकरण और प्रमाण-पत्र, जन्म प्रमाण-पत्र, जन्म प्रमाण-पत्र सुधार और दुकान एवं स्थापना पंजीकरण संबंधी दस्तावेज़ मितान सेवा से प्राप्त किये जा सकते हैं।
- इसी तरह मृत्यु प्रमाण-पत्र सुधार, विवाह प्रमाण-पत्र सुधार, आधार कार्ड पंजीकरण, (5 वर्ष तक के बच्चों का) आधार कार्ड में पता एवं मोबाइल नंबर में सुधार, नया राशन कार्ड बनवाने, राशन कार्ड ट्रांसफर/सरेंडर, राशन कार्ड सुधार, नया राशन कार्ड एपीएल, राशन कार्ड गुम केस, राशन कार्ड में नाम जोड़ना/काटना, नया बीपीएल राशन कार्ड बनाने की सुविधा इस योजना के तहत प्रदान की जा रही है।
- नागरिकों को मुख्यमंत्री मितान योजना से लाभान्वित होने के लिये योजना के टोल-फ्री नंबर 14545 पर कॉल करना होता है। इसके बाद अप्वाइंटमेंट बुक किया जाता है। तय समय और तारीख को मितान आवेदक के घर पहुँचकर आवश्यक दस्तावेज़ प्राप्त करते हैं और टैबलेट के माध्यम से दस्तावेज़ों को सत्यापित कर पोर्टल पर अपलोड करते हैं।
- इसके बाद सत्यापित दस्तावेज़ों को संबंधित विभागों को ऑनलाइन भेजा जाता है, जो आवेदक से संबंधित दस्तावेज़ की समीक्षा के बाद प्रमाण-पत्र जारी करते हैं। प्रमाण-पत्र जारी होने के बाद मितान द्वारा प्रमाण-पत्र आवेदक के घर पहुँचा दिया जाता है।

राज्य शासन ने 15 नवीन शासकीय महाविद्यालय स्थापना को दी स्वीकृति

चर्चा में क्यों ?

20 जून, 2023 को छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य शासन ने 2023-24 मुख्य मद में किये गए प्रावधानों के तहत प्रदेश में 15 नवीन शासकीय महाविद्यालय की स्थापना के लिये स्वीकृति प्रदान की है।

प्रमुख बिंदु

- जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभा में दिये गए बजट भाषण में की गई घोषणा को अमल में लाते हुए छत्तीसगढ़ के दूरस्थ इलाकों सहित अन्य जगहों में कॉलेज की स्थापना के लिये राज्य शासन द्वारा स्वीकृति दी गई है।

- इसके साथ ही स्वीकृत प्रति महाविद्यालय के लिये 33 पदों के मान से 495 पदों के सृजन की स्वीकृति के साथ ही कक्षाएँ प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है।
- राज्य शासन के द्वारा स्वीकृत नवीन महाविद्यालय के नाम-
  - नवीन शासकीय महाविद्यालय मर्दापाल, विकासखंड कोंडागांव, ज़िला कोंडागांव;
  - नवीन शासकीय महाविद्यालय, जेवरतला, विकासखंड डौंडीलोहरा, ज़िला बालोद;
  - नवीन शासकीय महाविद्यालय, चिल्हाटी, विकासखंड अंबागढ़ चौकी, ज़िला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी;
  - नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय, ज़िला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी;
  - नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय, ज़िला गरियाबंद;
  - नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय, ज़िला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही;
  - नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय, ज़िला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई;
  - नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय, ज़िला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर;
  - नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय, ज़िला सारंगढ़-बिलाईगढ़;
  - नवीन शासकीय महाविद्यालय कुंडा विकासखंड पंडरिया, ज़िला कबीरधाम;
  - नवीन शासकीय महाविद्यालय केरा विकासखंड नवागढ़, ज़िला जांजगीर-चांपा;
  - नवीन शासकीय महाविद्यालय अर्जुनी, विकासखंड डोंगरगांव, ज़िला राजनांदगांव;
  - नवीन शासकीय महाविद्यालय अमलीडीह रायपुर, ज़िला रायपुर;
  - नवीन शासकीय महाविद्यालय माना कैंप रायपुर, ज़िला रायपुर;
  - नवीन शासकीय महाविद्यालय अकलतरी विकासखंड बिल्हा, ज़िला बिलासपुर।

'देखो बस्तर सीजन 2-बस्तर ऑन बाइक'

चर्चा में क्यों ?

18-20 जून, 2023 तक छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान द्वारा 'देखो बस्तर सीजन 2-बस्तर ऑन बाइक'का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड, बस्तर एवं स्थानीय सहयोगी संस्थाओं के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ एवं सीमावर्ती राज्यों के 60 राइडर्स ने भाग लिया और बस्तर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये मोटर सर्किट पूरा किया।
- कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक धम्मशील गणवीर ने बताया कि 'बस्तर ऑन बाइक' का मुख्य उद्देश्य राइडर्स के माध्यम से बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता एवं पहुँच मार्ग, सड़कें, सुविधाएँ पर्यटकों को दिखाना एवं पर्यटन को बढ़ावा देना है।
- राइडर्स 'देखो बस्तर राइड'का प्रारंभ 18 जून को मां दंतेश्वरी मंदिर जगदलपुर से करते हुए कुरंदी, गुमलवाड़ा, कोलेंग होते हुए तीरथगढ़ पहुँचे। इसके उपरांत 19 जून को सभी राइडर्स तीरथगढ़ से कटेकल्याण होते हुए दंतेवाड़ा, बारसूर, कोरलापल के रास्ते चित्रकोट पहुँचकर मोटर सर्किट को पूरा किया।
- इस आयोजन के समापन समारोह में 19 जून को छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के द्वारा वेलनेस टूरिज़्म को बढ़ावा देने हेतु एक कार्यशाला का भी आयोजन किया। जिसमें मास्टरशेफ विजय शर्मा ने मिलेट्स जैसे कोदो, कुटकी, रागी आदि के फायदे एवं पकवानों के बारे में जानकारी दी।

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग की नवीन पहल : अपीलार्थी सुनवाई के लिये अब मोबाइल से जुड़ सकेंगे

चर्चा में क्यों ?

21 जून, 2023 को छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने एक नवीन पहल की शुरुआत की है, जिसमे अपीलार्थी अब मोबाइल के द्वारा भी द्वितीय अपील की सुनवाई में जुड़ सकेंगे। इससे घर बैठे या अन्य किसी स्थान से अपीलार्थी सीधे द्वितीय अपील की सुनवाई में मोबाइल की सहायता से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपस्थित रह सकते हैं।

प्रमुख बिंदु

- छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में ट्रायल बेस पर इसकी शुरुआत की गई है। राज्य सूचना आयुक्त मनोज त्रिवेदी और राज्य सूचना आयुक्त धनवेंद्र जायसवाल के कोर्ट में आज कई प्रकरणों की सुनवाई में इसका ट्रायल किया गया।
- आरटीआई के तहत द्वितीय अपील की सुनवाई में बिलासपुर से ठाकुर नवल सिंह और कांकेर से देवाशीष के कई प्रकरणों की सुनवाई की गई। इसमें अपीलार्थी अपने मोबाइल से सुनवाई में शामिल हुए। अपीलार्थियों को घर बैठे सुनवाई का अवसर प्राप्त हुआ।
- राज्य सूचना आयुक्त मनोज त्रिवेदी ने अपीलार्थियों से कहा कि वे मोबाइल कनेक्शन के माध्यम से जुड़ने के लिये बेहतर नेटवर्क का इस्तेमाल करें, ताकि ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी अच्छी मिले।
- राज्य सूचना आयुक्त धनवेंद्र जायसवाल ने बताया कि अभी तक राज्य सूचना आयुक्त के न्यायालय कक्ष में अथवा संबंधित ज़िलों के कलेक्टोरेट स्थित एनआईसी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष से अपीलार्थी सुनवाई में शामिल हो रहे थे। अब मोबाइल से भी शामिल होने का अवसर व सुविधा मिल सकेगी।
- छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के सचिव जी.आर. चुरेंद्र ने बताया कि मोबाइल कनेक्शन से अभ्यर्थियों को राज्य सूचना आयोग द्वितीय अपील की सुनवाई में शामिल होने के लिये वर्तमान में ट्रायल बेस पर कार्य शुरू किया गया है। इसमें राज्य सूचना आयुक्त के कोर्ट से अपीलार्थियों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक लिंक भेजा जाएगा। उस लिंक के द्वारा अपीलार्थी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत द्वितीय अपील के प्रकरण में सुनवाई की तारीख में सीधे जुड़ सकेंगे।

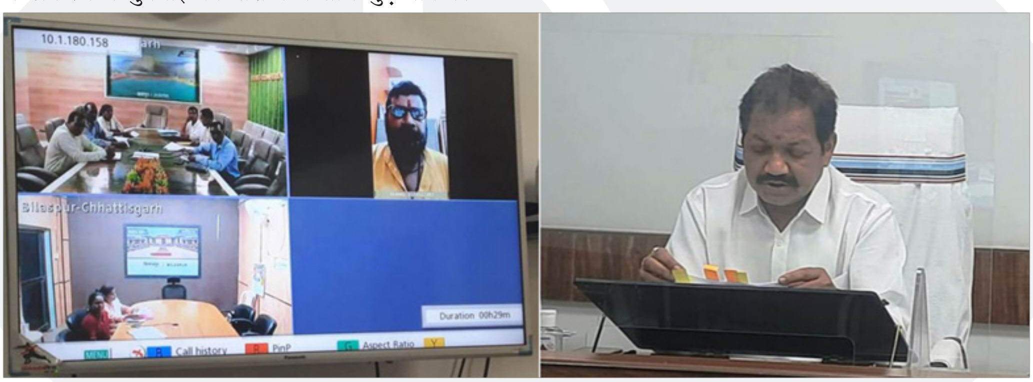

मुख्यमंत्री ने बालवाड़ी योजना के दूसरे चरण में 4318 बालवाड़ियों का शुभारंभ किया

चर्चा में क्यों ?

26 जून, 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बालवाड़ी योजना के दूसरे चरण में 4318 बालवाड़ियों का शुभारंभ किया। पहले चरण में प्रदेश में 5173 बालवाड़ी खुले थे।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि 5 सितंबर, 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नई शिक्षा नीति के अनुसार खेल-खेल में बच्चों के सीखने और समझने की क्षमता को विकसित करने के लिये प्रदेश में 'बालवाड़ी योजना'का शुभारंभ किया था।
- 'जाबो बालवाड़ी बढ़ाबो शिक्षा की गाड़ी'की थीम के साथ मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस योजना की शुरुआत की थी।
- स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बालवाड़ी योजना पाँच से छ: वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिये शुरू की गई है।
- 'बालवाड़ी योजना'के माध्यम से बच्चे को सीखने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है और उन्हें स्कूल के माहौल के लिये तैयार किया जाता है। बच्चों के लिये हर बालवाड़ी में आंगनबाड़ी सहायिका के अतिरिक्त संबद्ध प्राथमिक शाला के एक सहायक शिक्षक की भी तैनाती की जाती है और इसके लिये सहायक शिक्षक को हर माह 500 रुपए का अतिरिक्त मानदेय भी प्रदान किया जाता है।

- ‘बालवाड़ी योजना’ के प्रथम चरण में राज्य की 5173 आंगनबाड़ियों को बालवाड़ियों में बदला गया था, जिनके माध्यम से शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में राज्य के 5-6 साल के 3 लाख 23 हज़ार 624 विद्यार्थियों में से 68 हज़ार 54 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया था।
- बालवाड़ी के संचालन के लिये बच्चों की सामग्री ‘बाल वाटिका’ तैयार की गई है। बालवाड़ी का संचालन स्कूल परिसर में भोजन अवकाश के 2 घंटे पहले किया जाता है।

छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने वर्ल्ड बैंक ने मंजूर की 2460 करोड़ रुपए की राशि

चर्चा में क्यों ?

27 जून, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ के स्कूलों में बेहतर आधारभूत ढाँचे के साथ शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, सीनियर सेकेंडरी स्तर पर विज्ञान एवं वाणिज्य की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये वर्ल्ड बैंक ने छत्तीसगढ़ को लगभग 2460 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। इस परियोजना से गरीब और कमजोर वर्ग से आने वाले लगभग 40 लाख छात्र लाभान्वित होंगे।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा को मजबूत बनाने के साथ ही गरीब वर्ग के प्रतिभावान छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये स्वामी आत्मानंद इंग्लिश एवं हिन्दी माध्यम के उत्कृष्ट स्कूल प्रारंभ किये जा रहे हैं। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में अनेक नवाचारी पहल भी किये जा रहे हैं।
- सभी स्तरों में शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करने, सीनियर सेकेंडरी स्तर पर साइंस और कॉमर्स की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ एक्सीलरेटेड लर्निंग फॉर नॉलेज इकोनॉमी ऑपरेशन (चाक) परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में भी अध्ययन-अध्यापन की बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं।
- इसी कड़ी में वर्ल्ड बैंक की मदद से राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान और वाणिज्य शिक्षा को प्रोत्साहित करने, विज्ञान और गणित शिक्षकों की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ प्रयोगशालाओं में आवश्यक बुनियादी ढाँचे को मजबूत बनाने, दूरस्थ स्थानों से पढ़ाई के लिये आने वाले छात्रों के लिये आवास की व्यवस्था, स्कूलों में छात्रों का नामांकन दर बढ़ाने तथा गुणवत्तायुक्त शिक्षा के लिये प्रोजेक्ट तैयार किया गया है।
- वर्ल्ड बैंक की इस परियोजना से कक्षा 1 से 12वीं तक के लगभग 600 मॉडल स्कूलों को विकसित और संचालित करने में मदद मिलेगी तथा माध्यमिक स्तर पर विज्ञान और वाणिज्य की शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा।

नोट :

- स्कूलों में प्रशिक्षित शिक्षकों, मजबूत नेतृत्व और प्रबंधन सीखने के लिये पर्याप्त बुनियादी सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी। परियोजना से कोविड-19 के दौरान लर्निंग लॉस में कमी आएगी।
- परियोजना से अध्यापकों के प्रशिक्षण से शिक्षकों की कक्षा में अध्यापन की क्षमता बेहतर होने के साथ ही छात्रों की विषय-वस्तु को सीखने की क्षमता बढ़ेगी। इस परियोजना से छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ते निर्माण और सेवा क्षेत्रों में युवाओं के लिये रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे।

देश के आकांक्षी ज़िलों में नारायणपुर को मिला दूसरा स्थान

चर्चा में क्यों ?

28 जून, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में छत्तीसगढ़ के नारायणपुर ज़िले ने देश के 43 आकांक्षी ज़िलों में दूसरा स्थान हासिल किया है।

प्रमुख बिंदु

- नारायणपुर ज़िले को यह गौरवपूर्ण रैंकिंग बीते छह माह के दौरान जल जीवन मिशन के कार्यों का बेहतरीन क्रियान्वयन के लिये मिली है।
- गौरतलब है कि एक अक्टूबर 2022 से 31 मार्च, 2023 तक हुए जल-जीवन सर्वेक्षण 2023 में नारायणपुर को देश के आकांक्षी ज़िलों में दूसरा स्थान मिला है।
- विदित है कि जल जीवन मिशन में छत्तीसगढ़ राज्य की उल्लेखनीय प्रगति की सराहना पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार ने की है।

- बीते एक पखवाड़े में एक लाख 27 हज़ार से अधिक ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन प्रदाय किये जाने की उल्लेखनीय उपलब्धि भी छत्तीसगढ़ ने हासिल की है।
- गौरतलब है कि जल जीवन मिशन के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में 25 लाख 11 हज़ार 850 ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन दिये जाने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है जो कि घरेलू नल कनेक्शन दिये जाने के लक्ष्य का 50.13 प्रतिशत है।
- अब तक छत्तीसगढ़ राज्य के 556 गाँवों के शत-प्रतिशत परिवारों को भी घरेलू नल कनेक्शन दिया जा चुका है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत कुल 50 लाख 10 हज़ार 499 ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल प्रदाय किये जाने का लक्ष्य है।

स्वास्थ्य विभाग और टाटा ट्रस्ट ने मिलकर राज्य के 23 शहरी पीएचसी को बनाया मॉडल हमर अस्पताल

चर्चा में क्यों ?

28 जून, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और टाटा ट्रस्ट की सहयोगी संस्था सीआईएनआई (Collectives for Integrated Livelihood Initiatives) ने मिलकर प्रदेश के 23 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मॉडल हमर अस्पताल के रूप में विकसित किया है।

प्रमुख बिंदु

- इन मॉडल हमर अस्पताल से स्थानीय लोगों को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएँ मिल रही हैं। इन 23 में से 14 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (NQAS) प्रमाण पत्र से नवाज़ा जा चुका है।
- टाटा ट्रस्ट ने नवा रायपुर के श्री सत्य साईं संजीवनी अस्पताल के साथ मिलकर जन्मजात हृदय रोगों (Congenital Heart Disease) से पीड़ित बच्चों की स्क्रीनिंग एवं इलाज में भी सहयोग प्रदान किया है। ट्रस्ट के सहयोग से एक हज़ार बच्चों के ऑपरेशन हुए हैं।
- ट्रस्ट की मदद से चार शहरों जगदलपुर, बिलासपुर, राजनांदगाँव और रायपुर में जन्मजात हृदय रोगों के स्क्रीनिंग सेंटर भी संचालित हो रहे हैं।
- सीआईएनआई द्वारा छत्तीसगढ़ में संचालित मॉडल शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और टाटा ट्रस्ट की सीएचडी परियोजना का समापन कार्यक्रम आज नवा रायपुर स्थित एक निजी होटल में आयोजित किया गया।
- अस्पताल स्टॉफ के लिये 'वर्कप्लेस हैप्पीनेस (Workplace Happiness)' पर कार्यशाला के साथ ही 'शहरी आबादी के बीच प्रायमरी हेल्थ केयर'विषय पर पैनल डिस्कशन भी इस दौरान आयोजित किया गया।
- कार्यक्रम में सीआईएनआई द्वारा तैयार छत्तीसगढ़ में आदर्श हमर अस्पताल परियोजना पर आधारित पुस्तिका का विमोचन भी किया गया।
- विदित है कि राज्य शासन के साथ साझेदारी में टाटा ट्रस्ट द्वारा छत्तीसगढ़ हेल्थ सिस्टम्स स्ट्रेंथनिंग इनिशिएटिव (Chhattisgarh Health Systems Strengthening Initiative) के अंतर्गत वर्ष 2019 से मॉडल शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परियोजना संचालित की जा रही थी।
- इसके तहत राज्य के 23 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में बच्चों के अनुकूल मॉडल टीकाकरण कक्ष, रोगी-केंद्रित स्वास्थ्य केंद्र, डिजिटल तकनीकों के उपयोग, फॉर्मेसी सुदृढ़ीकरण, जाँच व दवाईयों की संख्या बढ़ाने तथा वहाँ कार्यरत स्टॉफ की कार्यदक्षता बढ़ाकर मॉडल हमर अस्पताल के रूप में विकसित किया गया है।
- राज्य के अन्य शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को भी इसी तर्ज पर मॉडल हमर अस्पताल के रूप में विकसित किया जाएगा। टाटा ट्रस्ट ने स्वास्थ्य सुविधाओं को सभी के लिये सुलभ बनाने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत जन्मजात हृदय रोगों (सीएचडी) से पीड़ितों की शीघ्र पहचान और उपचार के लिये भी श्री सत्य साईं संजीवनी अस्पताल के साथ मिलकर काम किया है।
- मॉडल हमर अस्पताल के रूप में विकसित अस्पताल-
    - रायपुर के भनपुरी, भाठागाँव, लाभांडी, राजातालाब, गुढ़ियारी, आमासिवनी, मठपुरैना, हीरापुर, कांशीराम नगर, देवपुरी और गोगाँव शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र,

नोट :

- दुर्ग ज़िले के बैकुंठधाम, न्यू खुर्सीपार, पोटिया कला और चरोदा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
- बिलासपुर ज़िले के गांधी चौक और राजकिशोर नगर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र,
- कोरबा ज़िले के ढोढ़ीपारा और गोपालपुर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र,
- कबीरधाम ज़िले का बूढ़ा महादेव शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र,
- अंबिकापुर ज़िले का नवापारा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र,
- कांकेर ज़िले का श्री राम नगर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र,

- उपरोक्त में से भनपुरी, भाठागाँव, राजातालाब, आमासिवनी, मठपुरैना, हीरापुर, चरोदा, गांधी चौक और राजकिशोर नगर, ढोढ़ीपारा और गोपालपुर, बूढ़ा महादेव, नवापारा, तथा श्री राम नगर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (NQAS) प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है।

नोट :